+-

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकः– प. 1(1)साप्र/2/2021 **जयपुर, दिनांकः** 5/5/22

–: आदेश :–

श्री इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस., आयुक्त, निवेश संवर्धन ब्यूरो, जयपुर, इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2044 है, को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर उनके निवास हेतु प्रथम श्रेणी राजकीय आवास संख्या 20–एफ, हीराबाग, जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) का निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता हैः–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस मे अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर मे ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (जीडी), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर को उनकी आई.डी क्रमांक एफ–22001449 दिनांक 2.05.2022 के क्रम में ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
5. आयुक्त, निवेश संवर्धन ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित आवंटी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष मे जमा कराना सुनिश्चित करावे।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,जयपुर शहर,/शासन सचिवालय जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
9. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–द्वितीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
11. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हीराबाग, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
13. निदेशक,उद्यानिकी जयपुर
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, हीराबाग जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
15. श्री नकाते शिवप्रसाद मदन, आई.ए.एस जिला कलेक्टर अलवर।
16. **श्री इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस., आयुक्त, निवेश संवर्धन ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड– द्वितीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।**
17. रक्षित पत्रावली।

05/05/22

संयुक्त शासन सचिव